

जनपद मेरठ से प्रयागराज (सी०एच०-7+900 से 601+847 कि०मी०) तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में एन०पी०वी० प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एन०पी०वी० के रूप में जनपद मेरठ से प्रयागराज (सी०एच०-7+900 से 601+847 कि०मी०) तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग के मार्ग में प्रयुक्त होने वाली संरक्षित वन भूमि 2.0342 हे० संरक्षित वन भूमि हेतु इको जोन क्लास-III ऑपन फोरेस्ट रु० 1228590.00 प्रति हे० की दर से रु० 2499198.00 की धनराशि का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा जमा की जायेगी तथा भविष्य में यदि एन०पी०वी० की जो भी दर निर्धारित होती है तो उक्त धनराशि भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा जमा किया जायेगा।

24/04/22
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग,
हापुड़।